पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 17, अंक 2/2016

आवश्यक है वित्तीय उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण

अमूमन यह देखा गया है कि आज भी आम उपभोक्ता अपने वित्तीय अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है और न ही उन्हें बैंकिंग नियमों की सही जानकारी होती है। उन्हें वित्तीय व्यवहार करते समय किसी भी पेपर पर बिना पढ़े और समझे हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए।

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी 'कट्स' द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक सहयोग से जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम के शुभारम्भ के अवसर पर जयपुर में आयोजित कार्यशाला में श्रीमती माधवी शर्मा, बैंकिंग लोकपाल, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुख्य अतिथि के रूप में उक्त जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारियों को भी वित्तीय व्यवहार करते समय ग्राहकों को उसके फायदे और जोखिम के बारे में जानकारी देनी चाहिए।

कार्यशाला में जॉर्ज चेरियन, निदेशक, कट्स ने अपने प्रारम्भिक उद्बोधन में कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भारतीय संसद में 2013 में दी गई जानकारी के अनुसार विभिन्न बैंकों में बिना दावों के खातों में जमा कुल राशि 3652 करोड़ रुपए है। जिनमें से 340 करोड़ रुपए निजी बैंकों एवं 75 करोड़ रुपए विदेशी बैंकों में जमा है। इन खातों में 10 सालों से कोई लेन-देन नहीं हो रहा।

कार्यक्रम में पी.के.प्रधान, महाप्रबंधक, बैंकिंग सुपरविजन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि रिजर्व बैंक की भूमिका ट्रस्टी की तरह है। दीपक गोगिया, सहायक प्रबंधक, रिजर्व बैंक ने पॉवर पॉइट प्रस्तुतिकरण देते हुए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की जानकारी देते हुए कहा कि जमाकर्ता को ब्याज सहित सम्पूर्ण राशि का दावा करने का अधिकार है। उन्होंने जमाकर्ता शिक्षा व जागरूकता के महत्व के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।

कार्यक्रम के तकनीकी सत्रों में मुनीष पी. कोठारी, चीफ काउंसलर, दिशा ट्रस्ट ने 'सुरक्षित बैंकिंग' सत्र में उपभोक्ता के अधिकारों की जानकारी देते हुए बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में विस्तार से बताया।

'उपभोक्ताओं के बैंकिंग अधिकार' सत्र में मुकेश ए. मेहरा, मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने शिकायत निवारण और नुकसान की भरपाई के अधिकार के बारे में और एक्सिस बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एस बालाचन्दर ने 'अपने ग्राहक को जानिए' सत्र में 'केवाईसी' योजना की विस्तार से जानकारी दी।

'बैंक में उपभोक्ता संरक्षण एवं शिकायत निवारण प्रणाली' सत्र में एन.के.शर्मा, मुख्य प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर ने शिकायतों का महत्व व उनके प्रकार के बारे में बताते हुए कहा कि बैंकों को जमाकर्ताओं की शिकायतों को बेहतर तरीके से लेकर यथासंभव उनका उचित समाधान करना चाहिए।

पंजाब नेशनल बैंक के महेन्द्र लोढ़ा ने 'ऑनलाइन बैंकिंग के अधिकार व आवश्यक जानकारी' सत्र में भागीदारों को ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल उपभोक्ताओं के अधिकारों, निजता व गोपनीयता संबंधित जानकारी दी। 'अनाधिकृत वित्तीय संस्थाओं में धन निवेश करने के खतरे' सत्र में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चन्द्रशेखर एस.एस. ने अनाधिकृत वित्तीय संस्थाओं में निवेश के खतरों से भागीदारों को अवगत कराया।

कार्यशाला के प्रारंभ में दीपक सक्सेना, वरिष्ठ कार्यक्रम समन्वयक ने सभी भागीदारों का स्वागत करते हुए परियोजना के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला में विभिन्न बैंकों के विषय विशेषज्ञ व अधिकारीगण, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, उपभोक्ता वर्ग व मीडिया प्रतिनिधियों सहित सौ से भी अधिक भागीदारों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

इस अंक में...

- सांसद चहेतों पर ही महरबान क्यों? 3
- कहां करें राशन दुकानों की शिकायत? 4
- हर विभाग में एसीबी के जासूस 5
- गरीबों में भी गरीब खोज लाई सरकार 7
- देश में बढ़ा अक्षय ऊर्जा उत्पादन 8

जीरो वेस्ट मैनेजमेंट पर किया मंथन

प्रदेश के नगर निकायों के चुने हुए महापौर और सभापतियों ने 'कट्स' इन्टरनेशनल की ओर से उदयपुर में आयोजित महापौर सम्मेलन में जीरो वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर विभिन्न विषयों पर मंथन किया। सम्मेलन का आयोजन स्वायत शासन विभाग एवं उदयपुर नगर निगम की सक्रिय भागीदारी में 'दि एशिया फाउण्डेशन' के सहयोग से 'सिटी मेयर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म' परियोजना के तहत किया गया। सम्मेलन में जयपुर, उदयपुर तथा कोटा के महापौर ने भाग लिया।

सम्मेलन में कोयम्बटूर के जीरो वेस्ट मैनेजमेंट को समझा गया और उसके तहत कार्य करने पर भी चर्चा की। हैदराबाद से आए विशेषज्ञ ए. पेरूमल ने जीआईएस बेस मेपिंग के द्वारा आर्थिक संसाधन बढ़ाने एवं चैन्नई की सत्यरूपा शेखर ने शहरी विकास के लिए डाटा बेस मैनेजमेंट की जानकारी दी।

महापौर नाहटा ने जयपुर में स्वच्छता को लेकर नगर निगम की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उदयपुर के महापौर चन्द्रसिंह कोठारी ने उदयपुर में डोर-टू-डोर व स्मार्ट सिटी को लेकर किए जा रहे कामकाज पर फोकस किया।

डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति के.के.गुप्ता ने बताया कि डूंगरपुर में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण का काम शुरू कर दिया गया है तथा प्रत्येक रविवार को जनता से फीडबैक लेने के लिए उनके मोबाइल पर निगम की ओर से संदेश भेजा जाता है।

सम्मेलन के प्रारंभ में 'कट्स' के परियोजना समन्वयक अमरदीप सिंह ने परियोजना के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मेयर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत किए जाने वाले सम्मेलनों का मकसद राजस्थान के शहरी निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा अपने अनुभवों को साझा करने और नवाचारों से सीख लेकर सकारात्मक बदलाव लाना है। सम्मेलन में डूंगरपुर के सभापति के.के. गुप्ता, बांसवाड़ा की सभापति मंजुबाला पुरोहित एवं कोटा की उप महापौर सुनिता व्यास ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में किए गए जा रहे कार्यों के बारे में बताया।

कृषि भूमि की उपजाऊ क्षमता का कम होना चिंताजनक

अधिकाधिक उपज लेने की लालसा के चलते रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाइयों के अंधाधुंध उपयोग से कृषि भूमि की उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है।

'कट्स' मानव विकास केन्द्र, चित्तौड़गढ़ की ओर से भैसरोड़गढ़ पंचायत समिति के बोराव व तंबोलिया में आयोजित ग्राम स्तरीय कार्यशाला में उक्त विचार उभर कर सामने आए। केन्द्र के समन्वयक गौहर महमूद ने बताया कि 'कट्स' द्वारा एसएसएनसी स्वीडन के सहयोग से चलाई जा रही प्रो-ऑर्गेनिक परियोजना के तहत यह कार्यशाला आयोजित की गई है। इस परियोजना का मूल उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना है। कृषि भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए किसानों को जैविक बीज, खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार जैविक खेती किसानों के आर्थिक विकास में मददगार साबित होगी।

'कट्स' जयपुर के धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ने बताया कि जिन जहरीले रसायनों का हम खेती में प्रयोग कर रहे हैं उनकी मात्रा मानव शरीर में बढ़ रही है । इससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और वे कई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं।

परियोजना अधिकारी राजदीप पारीक ने जैविक खेती से जुड़ी देशी तकनीकों पर प्रकाश डालते हुए केचुए की खाद, वर्मीवाश, जीवामृत व हर्बल स्प्रे आदि बनाने और उनके उपयोग के बारे में किसानों को विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर कृषि विभाग के अधिकारी सुशील कुमार ने किसानों को विभाग द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि जैविक खेती की प्रक्रिया को छोटे खेत से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। कार्यक्रम में परियोजना समन्वयक मदनलाल कीर ने परियोजना के तहत होने वाले आगामी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी।

आबादी 4 लाख, 'आधार' 14 लाख

प्रदेश के कई उपखंडों में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड बन गए। सरकारी आंकड़े प्रदेश की जनता में भ्रम पैदा कर रहे हैं। विभिन्न जिलों में कई उपखंड ऐसे हैं, जहां जनसंख्या से कई गुना अधिक आधार कार्ड बन गए। जयपुर जिले के कोटपूतली उपखंड की जनसंख्या 4 लाख है लेकिन इस क्षेत्र में 14 लाख से ज्यादा आधार कार्ड बने हैं।

ऐसी ही स्थिति अजमेर, उदयपुर, झुंझुनूं, कोटा आदि में भी है, जहां आधार कार्ड के आंकड़े देख लोग चकित हैं। हालांकि इसका कारण तकनीकी खामी को बताया जा रहा है। कुछ उपखंडों में आसपास के क्षेत्रों का डेटा भी शामिल हो गया है। फिर भी, सरकारी आंकड़े जो भ्रम फैला रहे हैं उन्हें दुरुस्त किया जाना चाहिए। *(रा.प., 05.05.16)*

सांसद चहेतों पर ही महरबान क्यों?

सांसद और विधायक कोटे से करवाए जाने वाले कार्यों की विश्वसनीयता पर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं। लाजमी भी है, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों में से ज्यादातर अपने कोटे की राशि कुछ चुनिंदा इलाकों और पंचायतों में ही खर्च कर रहे हैं। हाल ही ग्रामीण विकास विभाग की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई जानकारी में भी इसकी पुष्टि हो चुकी है।

इतना ही नहीं पिछले दिनों विधानसभा में भी सार्वजनिक तौर पर सामने आ चुका है कि राज्यसभा सांसद अश्क अली टांक और नरेन्द्र बुढ़ानिया ने भरतपुर की एक ही पंचायत के लिए ढाई करोड़ के ऐसे कामों की अनुशंषा कर दी, जिनमें से बहुत से काम सरकार की दूसरी योजनाओं में पहले ही हो चुके हैं। यह तो एक बानगी है, कई राज्यसभा व लोकसभा सांसद भी ऐसा ही कर चुके हैं। *(दै.भा., 21.04.16)*

शौचालय बने पर पानी का टोटा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2019 तक खुले में शौच जाने की व्यवस्था पूरी तरह खत्म करने की घोषणा की है। इस मिशन को सफल बनाने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है। इससे जनता की सोच बदली है और गांव-गांव व ढाणी-ढाणी में शौचालय बन गए। लेकिन इस मिशन की सफलता पर पानी की किल्लत भारी पड़ रही है।

देशभर में पानी के संकट के चलते गांवों में करीब 58 प्रतिशत शौचालयों का उपयोग ही नहीं हो रहा है। राजस्थान में पहले ही पानी की मारामारी है। गांवों के हालात तो और भी खराब हैं। राज्य में सिर्फ 37 फीसदी शौचालयों में ही जल उपलब्ध है। शौचालय होने के बावजूद लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। *(रा.प., 10.05.16)*

किसानों को नहीं मिली राहत

प्रदेश में पिछले एक साल में तीन फसलों पर लगातार प्रकृति की मार पड़ी। इससे किसानों की खड़ी फसलें तबाह हुई। उन्हें करीब 18 हजार 700 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा।

इस अवधि में प्रदेश के करीब 80 लाख से भी ज्यादा किसान फसली नुकसान से प्रभावित हुए। उनमें से मात्र 29 लाख किसानों को ही सरकारी सहायता मिल सकी है। करीब 51 लाख किसान अब भी सरकार की तरफ आस लगाए बैठे हैं। राज्य सरकार ने 19 जिलों के करीब 15 हजार गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर रखा है, लेकिन मुआवजा नहीं मिलने से किसानों की हालत ठीक नहीं है। *(द-ै.भा., 04.05.16)*

आदर्श गांव चुनने की रफ्तार धीमी

ऐसा लगता है कि इस बार भी प्रदेश में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत आदर्श गांव चुनने में विधायक रुचि नहीं ले रहे हैं। नए वित्तीय वर्ष में विभाग के मांगने पर भी ज्यादातर विधायकों ने अभी तक गांव के नाम तक नहीं सुझाए हैं।

पिछली बार भी विधायकों की धीमी रफ्तार के चलते चुने गए कई गांवों में अभी तक विकास के स्वीकृत कार्य पूरे होने की बाट जोह रहे हैं। आधे से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में तो विधायक साल के खत्म होने तक केवल आदर्श ग्राम का नाम ही सुझाते रहे थे। इसके बाद भी बजट जारी करने में हुई देरी से आदर्श गांव विकास से महरूम रहे और अभी तक बदहाली का शिकार हैं। विधायकों की रुचि नहीं होने से एक अच्छी योजना को पंख नहीं लग पा रहे हैं। *(दै.न., 14.06.16)*

वर्ल्ड बैंक ने दिया पर खर्च में कंजूसी

वर्ल्ड बैंक ने वर्ष 2012 में राजस्थान एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव प्रोजेक्ट के लिए 832 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। लेकिन अब तक इस प्रोजेक्ट पर सिर्फ 19 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। यह प्रोजेक्ट 2019 तक पूरा होना है। मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव कई बार इस प्रोजेक्ट की समीक्षा कर चुके हैं, लेकिन नतीजा अभी भी सिफर है।

इस प्रोजेक्ट का पैसा कम पानी वाली खेती को बढ़ावा देने पर खर्च किया जाना है। छोटे किसानों को इसमें वित्तीय सहायता दिए जाने का भी प्रावधान है, लेकिन अब तक तो इस प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चरिंग ही नहीं हो सकी है। प्रोजेक्ट जयपुर, गंगानगर, नागौर, अजमेर, टोंक, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, झालावाड़ और कोटा के लिए है। इससे 55 हजार किसानों को फायदा मिलना है। *(दै.भा., 08.06.16)*

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना

इंदिरा आवास योजना का नाम बदल कर अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया है। इंदिरा आवास योजना में पिछले तीन साल से प्रदेश में करीब 42 हजार आवास आधे-अधूरे पड़े हैं।

योजना में अफसरों की लापरवाही और मकान बनाने की इस लाचार रफ्तार के चलते गरीबों को समय पर मकान नहीं दिए जा सके। अब राज्य में संचालित 'ग्राम उदय से भारत उदय' अभियान के तहत इन अधूरे आवासों को पूरा कराने का फैसला किया गया है। *(दै.न., 19.04.16)*

कई विभाग सूचनाएं देने में फिसड्डी

'सूचना का अधिकार कानून' के तहत प्रदेश के कई महकमों में अधिकारी जनता को मांगी गई सूचनाएं देने से कतराते हैं। इससे सूचनाएं लेना अपने आप में एक 'टेढ़ी खीर' बनता जा रहा है। काफी जूतियां घिसने के बाद भी निर्धारित अवधि में सूचनाएं नहीं मिलने पर लोग 'राज्य सूचना आयोग' में दुबारा अपील करते हैं।

हालात यह है कि आयोग की ओर से संबंधित विभाग पर पैनल्टी लगाने या उसके खिलाफ कड़ी टिप्पणी करने के बाद ही सूचनाएं मुहैया हो पाती है। राज्य सूचना आयोग के अपीलीय अधिकारी को वर्ष 2014-15 में पेश की गई अपीलों की संख्या को देखें तो इनमें सबसे ज्यादा जनता से जुड़े महकमों से सूचनाएं नहीं मिलने की पाई गई हैं। इस अवधि में सूचना आयोग में 14 हजार 167 अपीलें दर्ज हुईं, जिनमें से 1328 अभी भी आयोग में विचाराधीन हैं। *(दै.न., 08.04.16)*

आवास पर कमाई की 'लक्ष्मण रेखा'

यदि आपकी सालाना आय तीन लाख रुपए से ज्यादा है तो राजस्थान सरकार आपको सस्ता आवास नहीं देगी। यहां तीन लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले को भी मध्यमवर्गीय माना गया है। जबकि केन्द्र सरकार की नजर में 6 लाख रुपए तक सालाना कमाई करने वाला व्यक्ति भी सस्ते आवास का हकदार है।

एक ही देश में आवास की दो अलग-अलग नीतियों की आड़ में मध्यमवर्गीय परिवार को ठगा जा रहा है। गंभीर बात यह है कि लाखों लोग इससे प्रभावित हैं लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। उधर डिमांड समझने में बिल्डर के साथ आवासन मण्डल भी नाकाम है। सस्ते आवास पर बैंक लोन ब्याज में करीब 1.50 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जाती है। लेकिन मध्यमवर्गीय को यह राहत नहीं मिल रही। *(रा.प., 05.06.16)*

राशन कार्ड से करोड़ों का गेहूं ब्लैक

श्रीगंगानगर के कई वार्डों में दोहरे राशन कार्ड बनवाकर राशन डीपो को उनका डबल राशन आवंटित किया। फिर डिपो संचालकों ने उस राशन को ब्लैक में बेच दिया। करीब डेढ़ करोड़ रुपए का केरोसिन व 46 लाख रुपए का गेहूं इन कार्डों की एवज में उठाया गया।

मामला तब उजागर हुआ जब मुखर्जी नगर निवासी महेन्द्र कुमार ने हनुमानगढ़ डीएसओ सुनिल वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अब वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में डीलरों के साथ मिलकर दो करोड़ रुपए का केरोसिन व गेहूं ब्लैक में बिकवाने का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि सुनिल वर्मा ने श्रीगंगानगर में ईओ रहते इस कारनामें को अंजाम दिया।

(दै.भा., 04.05.16)

बीज निगम से किसानों का मोह भंग

राजस्थान बीज निगम से किसानों का मोहभंग हो गया है। बीज निगम की ओर से कुछ मात्रा में बीज किसानों से तैयार कराया जाता है, लेकिन बड़ी मात्रा में बीज दूसरे राज्यों से मंगवाया जाता है। बाहर में मंगवाए गए बीज की गुणवत्ता की कमी के चलते इसका सीधा नुकसान किसानों को भुगतना पड़ता है।

किसानों का मानना है कि बाहर से आने वाले बीज की गुणवत्ता की जांच में मिलीभगत का खेल चल रहा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों विधानसभा में विधायक विद्याशंकर ने मामला उठाया था कि बीज निगम की ओर से किसानों को वितरित किया गया बीज अच्छी गुणवत्ता का नहीं है, इससे किसानों की फसल चौपट हो गई। बावजूद इसके कोई सुधार नहीं हो रहा। *(दै.न., 03.04.16)*

केरोसिन में बंदरबांट का खेल

प्रदेश में गरीब के तेल में करोड़ों रुपए की बंदरबांट पर लगाम कसने के सरकारी दावे दिखावा साबित हो रहे हैं। एलपीजी में सफल प्रयोग के बाद केरोसिन में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना लागू होनी है, लेकिन केरोसिन में जारी मिलीभगत के खेल के चलते अभी तक प्रदेश में इसकी शुरुआत भी नहीं हुई है।

कभी डेटाबेस की अनुपलब्धता तो कभी केरोसिन के पात्र परिवारों की अन्य सूचनाओं के अभाव का तर्क देकर खाद्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी योजना के क्रियान्वयन में लगातार देरी किए जा रहे हैं।

जिम्मेदार अधिकारी खुद करोड़ों रुपए की हो रही केरोसिन की काला बाजारी से वाकिफ हैं, लेकिन योजना को प्रभावी रूप से लागू करने में लगातार लेटलतीफी बरती जा रही है। *(रा.प., 20.06.16)*

कहां करें राशन दुकानों की शिकायत?

राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा, राशन की कालाबाजारी, दुकान नहीं खुल रही, स्कूलों में मिड डे मील अच्छा नहीं मिलता जैसी कई समस्याएं हर दिन सामने आती हैं। इसके लिए सरकार ने जिलों में करीब तीन साल पहले शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किए, खाद्य आयोग भी बनाया लेकिन यह सब कागजी ही नजर आ रहे हैं। हालात यह है कि आयोग को पता ही नहीं है कि जिलों में शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त भी हो गए हैं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हेमसिंह भडाना को भी इसकी जानकारी नहीं है। आमजन की भी स्थिति ऐसी ही है, तभी तो 33 माह बाद भी एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई है। खाद्य सुरक्षा कानून का जिम्मा संभाल रहे एक अधिकारी से पूछा गया तो जवाब ने चौंका दिया। अधिकारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सितम्बर 2013 में जिला कलेक्टरों को जिला शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त कर दिया गया था। अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। लेकिन अभी तक कोई शिकायत इनके पास नहीं आई। *(रा---प., 18.06.16)*

भ्रष्टाचार नहीं होगा बर्दाश्त

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जिला कलेक्टर एवं एसपी कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य प्रशासन में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर चिंता जताते हुए चेतावनी दी है कि अब भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा।

उन्होंने प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों से कहा कि आप जिलों में राज्य सरकार का चेहरा हैं और आपका प्रत्येक कार्य राज्य सरकार की कार्यप्रणाली को प्रतिबिम्बित करता है। उन्होंने अधिकारियों को लापरवाही, भ्रष्टाचार और निष्क्रियता के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की चेतावनी देते हुए कहा कि आपके कार्यों पर सरकार की पूरी निगाह है। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रदेश की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पर प्रकाश डालते हुए उन्हें तत्परता से पूरा करने के निर्देश दिए। *(न.ज्यो., 05.05.16)*

इस ग्राम पंचायत में सिर्फ भ्रष्टाचार

बांसवाड़ा जिले की चिकली ग्राम पंचायत। यहां कागजों में करोड़ों रुपए के काम हुए हैं लेकिन जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इनका भौतिक सत्यापन किया तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं मिला। इस पंचायत में 53 योजनाओं में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया। हैंडपंप लगवाने से लेकर सड़क और पुलिस के कामों में घोर अनियमितता मिली।

काम हुए बिना ही करोड़ों रुपए का भुगतान उठा लिया गया। इस पंचायत की जांच में ब्यूरो अधिकारियों को ढाई महीने लग गए। अब सरपंच, पूर्व सरपंच, सचिव, एईएन, जेईएन सहित आठ पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। *(दै.भा., 03.06.16)*

खुलेंगे कई भ्रष्टाचार के राज

राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के घोटालों और भ्रष्टाचार के कई राज अभी आगामी दिनों में कैग (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) की स्पेशल परफोर्मेंस ऑडिट जांच में खुल सकते हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रोजेक्ट्स में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार की पोल खोलने के बाद केन्द्र सरकार ने कैग से राजस्थान में मिशन की चार साल की जांच का फैसला किया है।

पूर्व अतिरिक्त मिशन निदेशक व आईईसी निदेशक आईएएस अफसर नीरज के.पवन, अतिरिक्त निदेशक अनिल अग्रवाल, लेखाधिकारी दीपा गुप्ता और उसके बाद चीफ इंजीनियर भुवनेश माथुर सहित अन्य अफसरों को रंगे हाथों भ्रष्टाचार में पकड़े जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। कैग की जांच में और भी कई मामले उजागर हो सकते हैं। *(दै.न., 20.06.16)*

हर विभाग में एसीबी के जासूस

एसीबी अधिकारी और कर्मचारी अब पीड़ित के बजाय खुद ही घूम-घूम कर अलग-अलग विभागों के ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, जो बिना रिश्वत के काम नहीं करते हैं। महीनों फाइल को अटकाए रहते हैं। इसका नतीजा है कि पिछले कुछ अर्से में जयपुर में एसीबी ने कलेक्टर, नगर निगम, जेडीए, खान विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग और अन्य विभागों में ट्रैपिंग की कार्रवाई की है।

एसीबी सूत्रों के मुताबिक मुख्यालय पर एसीबी चौकी पर तैनात कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल को पीसी एक्ट की धाराओं की ट्रेनिंग दी गई है। उन्हें निर्देशित किया गया हैं कि वे हर विभाग में सैम्पलिंग करें। जहां से भी जो जानकारी मिलती है, उसका सत्यापन करें व संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखें। *(रा.प., 06.04.16)*

घूस डकारने से पहले दबोचे रिश्वतखोर

प्रदेश में घूसखोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह लाखों रुपए की रिश्वत लेने से नहीं चूक रहे। सरकारी पगार लेने वाले ये घूसखोर आमजन से रुपए लिए बिना काम ही नहीं करते और लाखों रुपए हजम कर जाते हैं। यदि जनवरी 2016 से अप्रेल 2016 की बात की जाए तो करीब 25 लाख रुपए अधिकारी और कर्मचारी डकारने की फिराक में थे।

एसीबी ने पीड़ितों की शिकायत पर आरोपियों को समय पर दबोचा और यह राशि बचा ली। इसके अलावा जनवरी से मार्च तक तीन घूसखोरों से करीब 20 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। इन पर एसीबी द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति का मामला दर्ज किया गया। *(दै.न., 23.05.16)*

भ्रष्टाचार की कमाई तो रियायत नहीं

वित्त मंत्रालय की घरेलू कालाधन घोषणा योजना के तहत 30 सितम्बर तक लोगों को अपनी अघोषित आय का खुलासा करने का समय दिया गया है। यह आखिरी मौका है। इसके बाद अघोषित आय का ब्योरा नही देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मंत्रालय ने कहा है कि जिन लोगों ने भ्रष्ट गतिविधियों के जरिए धन कमाया है वे घरेलू कालाधन घोषणा योजना का फायदा नहीं उठा सकेंगे। यह योजना भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 के तहत दंडनीय अपराध के किसी अभियोजन के संबंध में लागू नहीं होगी। *(दै.भा., 21.06.16)*

एसीबी ने बदली रणनीति

इसे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की इच्छा शक्ति कहिए या नई रणनीति का नतीजा, इस साल अब तक एक भी कार्रवाई फेल नहीं हुई। जनवरी से अब तक हुई 102 कार्रवाई में कोई भी मामला ऐसा नहीं आया, जिसमें एसीबी टीम के पहुंचने से पहले ही आरोपित खिसक लिया हो और टीम को बैरंग लौटना पड़ा हो। चार-पांच मामले ऐसे जरूर हैं, जिनमें आरोपित ने रिश्वत लेने का दिन बदल दिया हो और कार्रवाई नहीं हो पाई।

अब एसीबी मुख्यालय में अधिकारियों को कोई शिकायत या सूचना मिलती है और उसे ट्रेप करना होता है तो चुनिंदा अफसर रणनीति बनाते हैं। पूरी टीम को मुख्यालय में एकत्र करने के बजाय जो जहां होता है, उसे वहीं से मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए जाते हैं। ऐसे में टीम का नेतृत्व करने वाले अधिकारी के साथ कुछ चुनिंदा लोगों को ही कार्रवाई का पता होता है। अन्य सदस्यों को भनक तक नहीं होती कि कहां जा रहे हैं, किसे पकड़ना है। उन्हें तो कार्रवाई होने पर ही पता चलता है कि फलां दफ्तर में फलां व्यक्ति को रिश्वत लेते पकड़ा गया है। *(दै.भा., 27.05.16)*

कारोबारियों ने उजागर किया कालाधन

देशभर में कालाधन सरेंडर कराने की केन्द्र सरकार की योजना के तहत प्रदेशभर में पिछले 24 दिन में 9 कारोबारी सामने आए हैं। इन्होंने 11.50 करोड़ रुपए का कालाधन उजागर किया है। विभाग इनसे जुर्माना वसूलेगा। एक जून से शुरू हुई यह योजना 30 सितम्बर तक चलेगी।

गोपनीयता के तहत आयकर विभाग ने इन कारोबारियों के नाम उजागर नहीं किए हैं। आयकर विभाग को उम्मीद है कि अब कालाधन उजागर करने वाले कारोबारियों का यह आंकड़ा बढ़ेगा।

सितम्बर के बाद आयकर विभाग सख्ती दिखाएगा। 30 सितम्बर तक सरेंडर करने पर कालेधन की राशि पर 45 प्रतिशत राशि आयकर विभाग को देनी होगी। इसमें 30 प्रतिशत टैक्स और 15 प्रतिशत जुर्माना, सेस व अन्य कर सम्मिलित हैं। *(दै.भा., 25.06.16)*

घूस मत दीजिए मदद लीजिए

अक्सर लोग विभागों में अपना काम अटकने के डर से पैसे देकर काम निकलवाते हैं और घूस मांगने वाले की शिकायत नहीं करते। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने ऐसे लोगों की मदद के लिए नया तरीका निकाला है।

पीड़ित की शिकायत पर पहले एसीबी अधिकारी गहनता से विचार करते हैं। विधिक राय भी लेते हैं। पीड़ित को उसका काम कराने में मदद करते हैं। फिर रिश्वतखोर को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। एसीबी ट्रैपिंग से पहले हर पीड़ित की समस्या का समाधान खोजती है। वरिष्ठ अधिकारियों ने हर जिले में बैठे अधिकारी और कर्मचारियों को यह निर्देश दिए हैं कि पीड़ित की समस्या को पहले जांच परख लें। *(रा.प., 10.04.16)*

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
जोधपुर	मोहम्मद तलजीम सुनील पुरोहित	हैल्पर, जलदाय विभाग की चौकी, जूनी मंडी हैल्पर, जलदाय विभाग की चौकी, जूनी मंडी	30,000	दै.भा., *02.04.16*
जयपुर	भारत भूषण गोयल	एसडीएम, शाहपुरा कार्यालय, जयपुर	3,50,000	रा.प. एवं दै.न., *05.04.16*
जयपुर	धर्मसिंह मीणा कर्ण सिंह अहमद	कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, मोतीडूंगरी जोन लिपिक, नगर निगम, मोतीडूंगरी जोन संविदाकर्मी, बाहरी व्यक्ति	70,000	रा.प. एवं दै.भा., *08.04.16*
डूंगरपुर	भूपेन्द्र सिंह चौहान	कनिष्ठ तकनीकी सहायक, साबला पंचायत समिति	25,000	दै.न., *22.04.16*
अजमेर	के.के. गोयल रोहित जैन व विनोद	उपायुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण दलाल	25,000 15,000	रा.प., *28.04.16*
बाड़मेर	सत्य प्रकाश त्रिवेदी श्याम लाल	सहायक अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम, सिवाना हैल्पर, जोधपुर डिस्कॉम, सिवाना	10,000	दै.भा. एवं दै.न., *05.05.16*
करौली	अंतू लाल बनैसिंह	एएसआई, सदर पुलिस थाना, करौली दलाल, आखावाड़ा निवासी	50,000	दै.भा. एवं रा.प., *07.05.16*
चित्तौड़गढ़	कृष्णचंद राव	लिपिक, कृषि उपज मंडी, बड़ी सादड़ी	11,000	दै.न., *08.05.16*
राजसमंद	राजेन्द्र भारती लक्ष्मण सिंह	सहायक कृषि निदेशक, कृषि विभाग व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति, आंजना	2,75,000	रा.प., *13.05.16*
सीकर	श्रवणकुमार	एएसआई, रामगढ़ शेखावाटी थाना	15,000	दै.भा., *26.05.16*
उदयपुर	परमेश्वर चौधरी	जेईएन, पीडब्लूडी, कोटड़ा	28,000	दै.भा. एवं दै.न., *31.05.16*
पाली	कृष्णमोहन शर्मा हितेश मीणा	बैंकिंग सहायक, सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, पाली कैशियर, सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, पाली	30,000	रा.प., *11.06.16*
अलवर	महावीर प्रसाद	लाइनमैन, बिजली विभाग, नारायणपुर	25,000	दै.भा., *12.06.16*
श्रीगंगानगर	राजकुमार छाबड़ा	लिपिक, नगर पालिका, सूरतगढ़	80,000	रा.प. एवं दै.भा., *14.06.16*
जयपुर	सुरेश परेवा प्रवर्तन	निरीक्षक, जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए)	1,00,000	रा.प. एवं दै.न., *16.06.16*
प्रतापगढ़	देवी लाल खराड़ी	एईएन, पीडब्लूडी धरियावद, प्रतापगढ़	25,000	दै.भा., *24.06.16*
कोटा	धनराज मीणा	थानाधिकारी, बूढ़ादीत थाना, कोटा	16,000	दै.न., *27.06.16*

निर्मल चरित्र हो पवित्र आत्मा! भ्रष्टाचार का तभी खात्मा!!

देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनका एक सूत्री एजेंडा भारत को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। वह कभी भी देश को गलत रास्ते पर लेकर नहीं जाएंगे। उन्होंने राजग सरकार के दो वर्ष पूरे होने के जश्न पर एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के सत्ता में आने के दो सालों के भीतर जनता ने बदलाव देखा है। लोगों को भरोसा है कि यह सरकार देश को आगे लेकर जा सकती है।

सरकार की विभिन्न उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए बजट में बड़ी राशि का प्रावधान किया है। अगर किसानों की जरूरतों को पूरा किया गया तो उनकी धरती सोना उगलेगी।

(दै.न., 30.05.16)

बनेगी जैविक कृषि नीति

केन्द्र की मोदी सरकार ने एक अप्रेल से किसानों को जैविक खेती के लिए बीस हजार रुपए प्रति हैक्टेयर अनुदान दिए जाने की घोषणा की है। इसके बाद प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 'जैविक कृषि नीति' बनाने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए एक समिति बनाई गई है। समिति अन्य राज्यों में बनाई गई जैविक कृषि नीति का अध्ययन कर रही है।

प्रदेश में अभी करीब चालीस हजार हैक्टेयर में जैविक खेती की जा रही है। इस पर राज्य सरकार आठ हजार रुपए प्रति हैक्टेयर का अनुदान दे रही है। सरकार चाहती है कि किसानों के फायदे के लिए अच्छी-अच्छी बातें जैविक कृषि नीति में शामिल की जाए। समिति कुछ क्षेत्र और फसलों का भी चयन कर रही है, ताकि सरकार और किसान का इस तरफ ध्यान केन्द्रित किया जा सके।

(दै.न., 02.06.16)

गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन

देश के इतिहास में पहली बार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय बीपीएल परिवार की महिलाओं को खाना पकाने के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराएगा। इसके लिए पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'उज्ज्वला' योजना की शुरुआत की है।

केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए आठ हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत तीन साल में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहे पांच करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। इससे महिलाओं के खाना बनाने में लगने वाले समय और श्रम की बचत के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य की रक्षा भी हो सकेगी।

(दै.भा., 02.05.16)

ठीक नहीं है मिट्टी की सेहत

हमारे खेतों की मिट्टी की सेहत ठीक नहीं है। पिछले एक साल से सॉयल हैल्थ कार्ड बनाने के लिए मिट्टी के जो साढ़े चौदह लाख नमूने लिए हैं, उनकी जांच रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आ रहे हैं। अभी तक चार लाख 71 हजार नमूनों की रिपोर्ट आई है। जांच में सामने आया है कि मिट्टी में आयरन, जिंक, व मैंगनीज जैसे पोषक तत्वों की भारी कमी है। इससे पैदावार और उगने वाले अनाज की ताकत घटी है।

सॉयल हैल्थ कार्ड की शुरुआत पिछले साल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की थी । किसानों को रिपोर्ट के आधार पर सॉयल हैल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं। अभी तक तीन लाख कार्ड वितरित हो चुके हैं। अब किसानों को जमीन की ताकत बढ़ाने के लिए सरकार देशी उपाय सुझा रही है। *(रा-.प., 19.06.16)*

सीमांत किसानों को 30 फीसदी ऋण

प्रदेश में लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए राज्य सरकार 30 प्रतिशत ऋण देगी। इसके लिए सरकार ने अल्पकालीन फसली सहकारी साख नीति जारी कर दी है।

सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ऋण राशि काश्तकार के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। नई फसली सहकारी ऋण नीति में कम से कम 30 प्रतिशत ऋण लघु व सीमांत किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। बंटाईदार काश्तकारों को भी ऋण सुविधा दी जाएगी।

(दै.न., 04.04.16)

प्रदेश का हर दूसरा किसान कर्जदार

राजस्थान में सूखा,ओले और अंधड़ जैसी विपदाओं की मार झेलने वाला हर दूसरा किसान कर्जदार है। उसके घर में न बीज है और न ही खाद के लिए पैसा। मजबूरन किसान खेती करने के लिए खाद, बीज सहित अन्य कृषि उपकरण के लिए बैंकों से कर्जा ले रहे हैं।

नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस की रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। प्रदेश में 100 में से 62 किसान कर्जदार हैं। देश के कर्जदार किसानों में राजस्थान का छठा नंबर है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 61.8 प्रतिशत किसान किसी न किसी के कर्जदार है। एक किसान पर औसत कर्ज 40 से 55 हजार रुपए के करीब है। *(रा.प., 05.06.16)*

गरीबों में भी गरीब खोज लाई सरकार

राजनीति में गरीब और गरीबी को लेकर भले ही आए दिन बहस हो जाती है। लेकिन, सरकार अब गरीबों में भी गरीब को ढूंढ लाई है। सरकारी आंकड़ों की माने तो प्रदेश में गरीबों में भी 1717 ऐसे परिवार हैं, जिन्होंने गरीबी की रैंकिंग में सबसे ज्यादा नम्बर लिए हैं।

इसके बाद की और भी श्रेणियां है, जिनमें सामाजिक और आर्थिक तौर पर एक के बाद एक निचले पायदान पर आ रहे परिवारों की रैंकिंग और संख्या तय है। सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों में गरीबी मापने के लिए लगाए सूचकांकों के आधार पर यह संख्या तय की गई है। माना जा रहा है कि भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबी की इसी वरीयता के आधार पर दिया जाएगा।

(रा.प., 10.05.16)

बिजली उत्पादन 17283 मेगावाट

ऊर्जा मंत्री पुष्पेन्द्र सिंह ने राज्य विधानसभा में जानकारी दी कि राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता 17283 मेगावाट हो गई है। जिसमें सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 1273 मेगावाट के करीब है। गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों की ऊर्जा उत्पादन क्षमता कुल 5267 मेगावाट है। उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान सरकार ने राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लि. का गठन किया है। इस कंपनी में प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा अध्यक्ष एवं सभी डिस्कॉम्स के एमडी सदस्य होंगे। इसके तहत मांग एवं उपलब्धता के आधार पर ही विद्युत का क्रय किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल में 5742 मिलियन यूनिट्स बिजली खरीदी और इसमें 3705 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि वर्तमान सरकार ने दो साल में सिर्फ 1432 मिलियन यूनिट्स की खरीद की और 3.31 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से 474 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। *(न.दु., 02.04.16)*

बीपीएल को मुफ्त बिजली कनेक्शन

प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बिजली कनेक्शन की आस लगाए बैठे हजारों परिवारों के लिए अच्छी खबर है। बिजली कंपनियां ऐसे गांवों में जरूरतमंदों को बिजली कनेक्शन देने के लिए विशेष शिविर लगा रही है। यह हर माह के पहले और तीसरे रविवार को लगाया जाएगा।

शिविर में ग्रामीण उपभोक्ताओं को मौके पर ही कनेक्शन जारी होंगे। ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन भी दिए जाएंगे। इस साल आठ लाख घरेलू परिवारों को कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है।

(रा.प., 25.05.16)

आदर्श उपभोक्ता को मिलेगा सम्मान

राजस्थान डिस्कॉम ने आदर्श उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें ऊर्जा मित्र सम्मान देने का निर्णय किया है जिससे सभी वर्गों के उपभोक्ताओं को प्रेरणा मिल सके।

डिस्कॉम के अध्यक्ष संजय मल्होत्रा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आदर्श उपभोक्ता वे ही माने जाएंगे जिन्होंने पिछले एक साल में बिजली का बिल समय पर जमा कराया है। इसके साथ ही सम्मान पाने के अधिकारी वे उपभोक्ता होंगे जिनके खिलाफ मीटर से छेड़छाड़ करने या वीसीआर भरे जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पहला ऊर्जा मित्र सम्मान समारोह सभी जिलों में सात जून को प्रताप जयंती के अवसर पर करने का निर्णय लिया है। इस दिन हर जिले में 11 आदर्श उपभोक्ताओं को चांदी के पदक से सम्मानित किया जाएगा। *(दै.न., 08.05.16)*

बिजली चोरी में नेता भी शामिल

केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने बिजली चोरी करने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि लाइनमैन से लेकर अधिकारी तक को रिश्वत दी जाती है। ऐसे में हो सकता है इस खेल में उद्योग के साथ नेता भी शामिल हों।

गोवा में बिजली मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि गरीब लोग बिजली चोरी में शामिल नहीं हैं। किसान भी ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि उसे पहले से ही सस्ती बिजली मिलती है। डिस्कॉम चेयरमैन श्रीमत पांडे ने अधिकारियों को आगाह किया है कि बिजली चोरी मामले में यदि अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आती है तो उन्हें नहीं बख्शा जाएगा।*(डे.न्यू. 17.06.16)*

किसानों का सहारा बनी सौर ऊर्जा

प्रदेश में किसानों को अब न बिजली गुल होने की चिंता सताती है और न ही दरें बढ़ने की। बिजली की बचत के साथ महंगे बिल से भी राहत मिली है। यह संभव हुआ है सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से। कई स्थानों पर किसान अब सोलर लाइट से ट्यूबवैल से सिंचाई समेत अन्य कई कृषि कार्य कर रहे हैं।

सरकार की तरफ से खेतों में लगने वाली इन सोलर प्लेट्स के लिए लगभग 70 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। खेतों में लगी इन सोलर प्लेट्स की गांरटी 10 से 15 साल की है। संबंधित टीम भी खेतों में आकर किसानों को सौर ऊर्जा प्लेट्स के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है और हर माह टीम इनकी मॉनिटरिंग करने भी आती है।

(रा.प., 30.05.16)

देशभर में एक दर पर बिजली

पूरे देश में अब अलग-अलग दर की जगह एक दर से बिजली उपलब्ध होगी। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि देश में 4.40 रुपए प्रति यूनिट बिजली दर लागू कर दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि विद्युत प्रवाह नाम से एक मोबाइल एप भी शुरू किया गया है। इस एप के जरिए लोग अब बिजली की उपलब्धता का भी पता लगा सकेंगे। एप आपको ग्रिड से बिजली किस दर से उपलब्ध है इसकी भी जानकारी देगी।

गोयल के मुताबिक, वह पूरे देश में एक समान बिजली दर का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश में जुटे हुए थे। एक ही दर पर बिजली उपलब्धता सरकार के वन नेशन, वन ग्रिड और वन प्राइस मिशन का हिस्सा है।

(रा.प., 07.04.16)

देश में बढ़ा अक्षय ऊर्जा उत्पादन

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की कुल क्षमता बढ़कर 42849.38 मेगावाट हो गई। इसके साथ ही यह पवन बिजली क्षेत्र की कुल क्षमता 42783.42 मेगावाट से आगे निकल गई है। वैसे 30 अप्रैल 2016 को देश की कुल स्थापित क्षमता 3 लाख मेगावाट पहुंच गई है।

आंकड़ों के अनुसार इसमें तापीय क्षेत्र की कुल उत्पादन क्षमता 211420.40 मेगावाट रही। पीडब्लूसी के कामेश्वर राव के अनुसार सौर तथा पवन ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को मजबूत केन्द्रीय नीति से फायदा हुआ है, साथ ही एक शुरूआती चरण में इन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश से लाभ मिला। सरकार ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 2022 तक 175000 मेगावाट बिजली क्षमता का लक्ष्य रखा है। इसमें 100000 मेगावाट सौर तथा 60000 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता शामिल है।

(दै.भा., 12.06.16)

पानी के दुरुपयोग को रोकने का कानून में प्रावधान

प्रदेश में पानी के दुरुपयोग को रोकने और जरूरतमंद को पेयजल मुहैया करवाने के लिए राज्य सरकार राजस्थान वॉटर एक्ट ला रही है। विभाग की ओर से इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस पर केबिनेट की मुहर लगेगी।

दरअसल, प्रदेश में पानी को लेकर किसी तरह का कोई कानून नहीं है। महज गाइडलाइन के जरिए ही पानी के उपयोग और दुरुपयोग को लेकर विभाग कार्य करता है। करीब आठ माह पहले विभागीय स्तर पर एक कमेटी बनी थी। कमेटी द्वारा विभिन्न राज्यों के वॉटर एक्ट का अध्ययन कर राज्य के लिए वॉटर एक्ट का मसौदा तैयार किया गया। इसमें मोटे तौर पर पानी के दुरुपयोग को लेकर सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही डार्क जोन में अति जलदोहन करने वालों पर भी शिकंजा कसने के नियम बनाए गए हैं। नियमों में जुर्माने से लेकर सजा तक का प्रावधान है। *(दै.न., 25.05.16)*

पानी का हो आर्थिक मूल्य तय

कुछ राज्यों की सूखे की स्थिति के बीच नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अमिताभ कान्त ने पानी को जिंस मानने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि पानी जैसे सीमित संसाधन का लोग सम्मान करें इसके लिए जरूरी है कि इसका आर्थिक मूल्य तय किया जाए। उन्होंने एक पैनल चर्चा में कहा कि जब तक आप पानी का मूल्य तय नहीं करेंगे, तब तक आप इसकी आर्थिक लागत नहीं पाएंगे। पानी के लिए तब तक सम्मान नहीं मिलेगा जब तक कि लोगों को इसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी।

उन्होंने कहा कि भारत में जल संभरण व संरक्षण के लिए बहुत कुछ करना है। पानी को फिर से इस्तेमाल लायक बनाने के लिए भी कार्य करना होगा। इसके लिए बेहतर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने कहा कि नीति निर्माताओं ने सरकार से पहले भी पानी का मूल्य तय करने की बात कही है। पूर्ववर्ती योजना आयोग भी इस मुद्दे की वकालत कर चुका है। *(न.नु., 08.05.16)*

अब लगेंगे नए पानी के मीटर

पानी की छीजत को कम करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जयपुर के चार क्षेत्रों में पानी के नए अत्याधुनिक मीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए जलदाय विभाग ने फरीदाबाद की आईट्रोन कंपनी का चयन किया है। कंपनी द्वारा लगाए जाने वाले मीटर जलदाय विभाग की सेंट्रल लैब में पास हो चुके है। जलदाय विभाग के अनुसार राजधानी में 60 फीसदी से ज्यादा मीटर खराब पड़े हैं।

कार्यादेश के बाद यह कंपनी चार माह में मानसरोवर, आदर्श नगर, चित्रकूट और बनीपार्क क्षेत्रों में करीब 12 हजार मीटर बदलने का काम शुरू करेगी। इसके बाद पानी की छीजत को लेकर पूरे शहर के लिए प्लानिंग तैयार की जाएगी। *(दै.न., 03.06.16)*

पानी की चोरी पर लगेगी रोक

अब पेयजल की चोरी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए हर जिले में एक विजीलेंस टीम का गठन किया जा रहा है। इस टीम में करीब आधा दर्जन अधिकारी शामिल होंगे। यह टीम अवैध कनेक्शनों की शिकायत पर आकस्मिक दौरा कर पेयजल चोरी करने वालों को पकड़ेगी। वह पानी की चोरी पर निर्धारित जुर्माना राशि वसूलेगी और संबंधित थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएगी।

जलदाय विभाग की ओर से पानी की चोरी पर अंकुश लगाने के लिए कानून भी लाया जा रहा है। कानून बनने के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी। इसमें सजा का भी प्रावधान है। *(दै.न., 02.04.16)*

गांवों में लगेंगे 25 लाख पौधे

प्रदेश में चल रहे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत प्रथम चरण में 5 माह में 90 हजार जल संरक्षण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। वहां बारिश के बाद जल भराव से वर्षा जल संरक्षित हो रहा है। अब दूसरे चरण में 3500 गांवों का चयन किया जाएगा। इसके लिए गांवों में जाकर नए जलग्रहण विकास कार्यों की कार्य योजना बनाई जा रही है।

अभियान के तहत प्रदेशभर में वृक्षारोपण भी शुरू किया गया है। साढ़े तीन हजार गांवों में करीब 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। इसके लिए वन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है एवं पौधे सालभर तक जीवित रहे इसकी जिम्मेदारी संबंधित जिला कलेक्टर को सौंपी गई है। *(दै.भा., 24.06.16)*

वॉटर हार्वेस्टिंग होगा मजबूत

प्रदेश में वॉटर हार्वेस्टिंग, एनिकट्स, फार्म पॉन्ड्स, परकोलेशन टैंक आदि का निर्माण करने के साथ ही भूजल के नए क्षेत्रों की खोज की जाएगी। कार्यक्रम के तहत स्प्रिंग पिलर, ड्रिप इरीगेशन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही पेयजल के लिए राज्य में गहराई के नलकूप बनाए जाएंगे।

जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी ने यह जानकारी देते हुए बताया इसके लिए नेशनल ग्राउंड वॉटर इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत विश्व बैंक की ओर से 1300 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया करवाई जाएगी। यह कार्यक्रम पांच साल का होगा। *(दै.न., 12.05.16)*

गांव से बाहर न जाए बारिश का पानी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अच्छी बरसात की खबर राहत देती है। लेकिन यह हमारे सामने एक मौका है और चुनौती भी। हम कोशिश करें कि बारिश का पानी गांव से बाहर न जाने पाए। बारिश का पानी बचाया जाना चाहिए।

इसके लिए गांव-गांव में जन आंदोलन चलाया जाना चाहिए। ग्राम पंचायतों को जन सहयोग से तालाब बनाने और भूजल को रिचार्ज करने के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा आज पानी की समस्या हमारे लिए सबसे बड़ा संकट है और इस संकट से तभी उबर सकते हैं, जब हर व्यक्ति पानी का संरक्षण करने का संकल्प ले। *(दै.भा., 25.04.16)*

समूहों के उत्पाद होंगे ऑनलाइन

राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों के बनाए उत्पादों को महिला ई-हाट ऑनलाइन बिक्री प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार खुद उत्पादों की जानकारी जुटाकर ऑनलाइन बिक्री के लिए सूचनाएं अपलोड करेगी। इसके लिए सभी जिलों में कार्यक्रम अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने छोटी महिला उद्यमियों के उत्पादों की बिक्री के लिए यह सेवा शुरू की है। इसका एक लिंक राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर भी होगा। इससे गांव-ढाणी में लघु उद्योगों के जरिए कमाने वाली महिलाओं को सम्बल मिल सकेगा। *(दै.न., 10.05.16)*

फूड सेफ्टी दायरे में होंगे महिला उत्पाद

महिला स्वयं सहायता समूहों के निर्मित खाद्य उत्पाद अब फूड सेफ्टी एक्ट के दायरे में बिक्री के लिए मान्य होंगे। राज्य सरकार ने ऐसे समूहों को फूड सेफ्टी एंड स्टैण्डर्ड एक्ट ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) में रजिस्ट्रेशन कराने की अनिवार्यता कर दी है।

महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री बढ़ने के साथ ही मिलावटी उत्पादों की शिकायतें लगातार बढ़ रही है। जांच में सामने आया है कि स्वयं सहायता समूहों की आड़ में विक्रेता बचने का प्रयास कर रहे हैं। कई जगह समूहों के नाम पर मिलावट करने वाले यह खेल रच रहे हैं। इसलिए विभाग ने रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता लागू की है। *(दै.न., 24.06.16)*

गरीब बच्चों पर हो ध्यान केन्द्रित

यूनिसेफ ने कहा है कि दुनिया को पिछले 25 वर्षों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए सर्वाधिक गरीब बच्चों की मदद करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

यूनिसेफ ने शिशु मृत्यु दर में आई 53 फीसदी की गिरावट और अत्यधिक गरीबी में आई नाटकीय कमी का जायजा लेते हुए चेतावनी दी है कि यदि पांच साल से कम आयु के सबसे कमजोर 6 करोड़ 90 लाख बच्चों पर प्रमुखता से ध्यान नहीं दिया गया तो वे ऐसे कारणों से मारे जाएंगे जिन्हें रोका जा सकता था और 16 करोड़ 70 लाख लोग आगामी 15 वर्ष में गरीबी से जूझेंगे।

यदि विश्वभर में ऐसी असमानताओं से निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया तो इसका विश्वभर के समाजों पर नाटकीय प्रभाव पड़ेगा और इससे अस्थिरता बढेगी। *(न.नु., 29.06.16)*

पालनहार योजना का मिलेगा लाभ

प्रदेशभर में अनाथ बच्चों को पालनहार योजना के तहत लाभान्वित करने की योजना तो है, लेकिन अनाथ बच्चों की पूरी जानकारी नहीं होने से योजना केवल कागजों में रह जाती है। प्रदेश की कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने इस बारे में राज्य सरकार को अवगत कराया है। इसके बाद सरकार ने इस बात को गंभीर माना है।

अब सरकार ने योजना के तहत ब्लॉक स्तर पर सर्वे कराने का निर्णय लिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एंव बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग इन बच्चों की सुध लेगा। इन बच्चों के स्कूल दाखिले का जिम्मा शिक्षा विभाग लेगा और पालनहार योजना का लाभ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग देगा। *(दै.न., 04.04.16)*

बाली उम्र में मां बन रही बालिकाएं

बेटियों को पढ़ाने- लिखाने, बाल विवाह रोकने के लिए दर्जनों योजनाओं पर हर साल करोड़ों रुपए फूंकने के बावजूद प्रदेश में आज भी हालात यह है कि हजारों लड़कियां कच्ची उम्र में ही मां बन रही हैं। इससे न सिर्फ जच्चा-बच्चा की शारीरिक व मानसिक दशा पर बुरा असर पड़ रहा है बल्कि समाज के लिए गंभीर स्थितियां भी खड़ी हो रही है।

समाज व सरकार को आइना दिखाती यह सच्चाई वार्षिक स्वास्थ्य सर्वे 2012-13 की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 35.3 और शहरी क्षेत्र में 37.5 प्रतिशत लड़कियां बालिग होने से पहले ही मां बन गई। *(रा.प., 11.06.16)*

हर जिले में बनेगा महिला मंच

राज्य के दूर-दराज के इलाकों में महिलाओं के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार, अत्याचार व शोषण की जानकारी राज्य महिला आयोग तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए महिलाओं की मदद के लिए महिला आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए पहली बार कोटा से जिला महिला मंच का गठन शुरू कर दिया है। जिससे महिलाएं कभी भी अपनी शिकायतें आसानी से दर्ज करवा सकेंगी।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा ने बताया है कि अब प्रत्येक जिले में महिला मंच का गठन होगा। मंच जिलों में होने वाली घटनाओं पर निगरानी रखेगा और तत्काल वस्तुस्थिति से आयोग को अवगत कराएगा। *(रा.प., 13.05.16)*

'स्टैंड अप इंडिया' का शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'स्टैंड अप इंडिया' योजना शुरू की है। योजना के तहत देशभर में फैली बैंकों की सवा लाख शाखाएं अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग के उद्यमियों को कारोबार के लिए एक करोड़ रुपए तक का कर्ज उपलब्ध कराएंगी।

योजना कार्यक्रम का तौर-तरीका समझाते हुए उन्होंने कहा कि इससे देशभर में नए उद्यमी पैदा होंगे। हर बैंक शाखा को नया उपक्रम लगाने के लिए 10 लाख से एक करोड़ रुपए तक के कम से कम दो ऋण बिना कुछ गिरवी रखे देने होंगे। यह योजना दलित से लेकर आदिवासी समुदाय तक लोगों का जीवन बदल देगी। इससे नौकरी ढूंढने वाले नौकरी देने वाले बन सकेंगे। *(न.नु., 06.04.16)*

सड़क सुरक्षा

देश में रोज होते हैं 1374 सड़क हादसे

देश में हर रोज करीब 1374 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें 400 लोग मारे जाते हैं और उनमें से 77 फीसदी घटनाओं के लिए चालक जिम्मेदार होते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की 'भारत में सड़क दुर्घटना-2015' नामक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक गत वर्ष देश में 5 लाख 1423 दुर्घटनाएं हुईं। इनमें 1 लाख 46 हजार 135 लोग मारे गए और 5 लाख 247 लोग घायल हुए। पिछले साल, 2014 के मुकाबले दुर्घटनाएं 2.5 फीसदी बढ़ी हैं और करीब 5 फीसदी अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि यह चिंता का विषय है कि दुनिया में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं भारत में होती हैं। उन्होंने कहा कि इन दुर्घटनाओं में काफी सुधार लाया जा सकता है और उनकी सरकार इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। सरकार मोटर वाहन कानून को और मजबूत बनाने के लिए विधेयक ला रही है। इसमें सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उपायों के सख्ती से पालन की व्यवस्था होगी। *(दै.भा., 10.06.16)*

दूरसंचार सेवाएं

नहीं मिलेगा कॉल ड्रॉप का पैसा

कॉल ड्रॉप के बदले आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। इस बारे में दूरसंचार नियामक ट्राई का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ट्राई का आदेश मनमाना, अनुचित और अपारदर्शी है। जस्टिस कुरियन जोसफ व जस्टिस आर.एफ. नरीमन की बेंच ने टेलीफोन कंपनियों की संस्था सीओएआई की याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है। इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्राई के फैसले को सही ठहराया था। एसोसिएशन ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

फैसले के बाद दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, अगर कंपनियां देश के कोने-कोने में सेवा का विस्तार कर सकती हैं तो वे क्वालिटी क्यों नहीं सुधार सकतीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब ट्राई को सोचना है। जहां तक सरकार का सवाल है वह कंपनियों को बेहतर सेवा देने के लिए कहती रहेगी। *(दै.भा., 12.05.16)*

पर्यावरण

सबसे प्रदूषित शहरों में आधे हमारे

विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्लूएचओ) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार ईरान का जबोल दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। वहीं दुनिया के टॉप टेन प्रदूषित शहरों में भारत के चार शहर मध्यप्रदेश का ग्वालियर, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद, बिहार की राजधानी पटना और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है।

वहीं टॉप 20 में भारत के कुल दस शहरों को शुमार किया जाता है। रिपोर्ट में ग्वालियर को दूसरे, इलाहाबाद को तीसरे, पटना को छठे और रायपुर को सातवें स्थान पर रखा गया है। दिल्ली को सूची में 11वां स्थान मिला है। रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में पहले की अपेक्षा प्रदूषण कम हुआ है। हालांकि इस दिशा में अभी काफी सुधार की जरूरत है।

सर्वे में 103 देशों के तीन हजार शहरों के माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर मसलन पी.एम. 2.5 और पी.एम. 10 स्तर को जांचा गया। वर्ष 2014 में दिल्ली में बारीक कणों के पी.एम. 2.5 का स्तर ज्यादा था। रिपोर्ट में बीजिंग का प्रदूषण बढ़ने और अमेरिका के शहरों में कम होने का भी जिक्र किया गया है। *(रा.प., 13.05.16)*

वित्तीय सेवाएं

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना नहीं भर सकी उड़ान

सरकार की स्वर्ण मुद्रीकरण योजना अभी लोकप्रिय नहीं बन पाई है। इसकी वजह बैंकों के द्वारा योजना का प्रचार-प्रसार न करने और संग्रहण केन्द्रों और रिफाइनरी के प्रमाणन की धीमी प्रक्रिया का होना है। कुछ बैंकों ने मंदिरों के सा बात-चीत कर उनकी प्रतिक्रिया जानी थी, लेकिन उसके बाद वे तेजी से कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं।

विशेषज्ञों से मिली जानकारी के अनुसार अब तक वित्त मंत्रालय की करीब 10 बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के बारे में चर्चा की गई। सरकार ने मंदिर ट्रस्टों की मांग मानी है। इसके बाद 8 मंदिरों ने योजना के तहत सोना जमा कराया है। हालांकि देश में अनुपयोगी पड़े सोने का तीन-चौथाई हिस्सा रखने वाले स्वर्ण धारक योजना को लेकर उत्साहित नहीं हैं और न ही पूरी तरह जागरूक। भारतीय परिवारों व मंदिरों के पास करीब 25 हजार टन सोना होने का अनुमान है। *(रा.प., 20.05.16)*

जन स्वास्थ्य

सुधरेगा स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा

जयपुर शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए सभी को चिकित्सा सेवाएं सुलभ कराने के उद्देश्य से शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा मजबूत किया जाएगा। इसके लिए चिकित्सा विभाग ने कवायद तेज कर दी है।

नेशनल हैल्थ मिशन के तहत जयपुर शहर में 28 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किया जाएगा। ये सभी केन्द्र उन क्षेत्रों में बनाए जाएंगे, जिनके नजदीक या आसपास झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग भी जीवनयापन करते हैं। इससे स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को भी आसानी से निःशुल्क इलाज मुहैया हो सकेगा। इन केन्द्रों पर प्राथमिक उपचार की सभी सुविधाएं मिलेंगी। इसमें सामान्य बीमारियों के ओपीडी इलाज के साथ ही ब्लड सैंपल लेकर मलेरिया जैसी सामान्य जांच की सुविधा मिलेगी। *(दै.न., 21.04.16)*

उपभोक्ता फैसले

ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज को भारी पड़ा बिस्किट के पैकेट का वजन कम होना

नागौर निवासी नन्दकिशोर तिवाड़ी ने 10 अक्टूबर 2014 को ब्रिटानिया बिस्किट का 400 ग्राम का पैकेट खरीदा था। इसका वजन 313 ग्राम ही निकला। इस पर उन्होंने जिला उपभोक्ता मंच नागौर में परिवाद दर्ज कराया। मामले की सुनवाई पर मंच ने ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लि.को दोषी माना और तिवाड़ी को 20 हजार रुपए मानसिक व्यथा और 15 हजार रुपए परिवाद खर्च के अदा करने के आदेश दिए। साथ ही पैकेट की कीमत और एक माह में राशि का भुगतान नहीं करने पर उस पर ब्याज देने के आदेश भी दिए।

ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज ने जिला मंच के फैसले के खिलाफ राज्य आयोग में अपील की। आयोग में सुनवाई पर ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज ने दलील दी कि मूल बिस्किट का पैकेट और बिल जिला मंच में पेश नहीं हुआ। जबकि आयोग ने पाया कि जिला मंच में बिस्किट का पैकेट पेश हुआ था, जिसका वजन 87 ग्राम कम पाया गया। मूल बिल नहीं होने की दलील को नकारते हुए आयोग ने कहा कि विवाद पैकेट के वजन का है न कि मूल बिल का। अपील महज उपभोक्ता को परेशान करने के लिए दर्ज की गई है। आयोग ने अपील को खारिज करते हुए ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लि. को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता नन्दकिशोर तिवाड़ी को परिवाद खर्च सहित 40 हजार रुपए अदा करे। *(रा.प., 26.05.16)*

सेवायतन अस्पताल को भारी पड़ा इलाज में लापरवाही बरतना

सुभाष कॉलोनी, झोटवाड़ा निवासी सत्यनारायण शर्मा ने 1998 में अपनी गर्भवती पत्नी का अजमेर रोड़ स्थित सेवायतन अस्पताल में इलाज कराया था। अस्पताल में 13 अक्टूबर को उसे डिलीवरी के लिए भर्ती किया गया। अस्पताल में जुड़वा बच्चों को जन्म देने में उनकी पत्नी की तबियत बिगड़ गई और खून की कमी हो जाने से उसकी मौत हो गई।

शर्मा ने खून की कमी होने और पूर्व से खून का इंतजाम नहीं किए जाने पर अस्पताल के खिलाफ जिला उपभोक्ता मंच जयपुर में परिवाद दर्ज कराया। जिला मंच ने मरीज की नाजुक स्थिति होने से पूर्व खून की व्यवस्था नहीं करने को अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और सेवा में दोष मानते हुए अस्पताल पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाया।

लेकिन अस्पताल ने राज्य आयोग में अपील कर दी। राज्य आयोग ने अस्पताल को राहत देने के बजाय हर्जाना राशि को बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दिया। इस पर सेवायतन अस्पताल मामले को राष्ट्रीय आयोग में ले गए और अपने को निर्दोष साबित करने का प्रयास किया। लेकिन राष्ट्रीय आयोग ने तथ्यों के आधार पर सेवायतन अस्पताल को दोषी पाया और हर्जाना राशि को दो लाख रुपए से बढ़ाकर साढ़े चार लाख रुपए करने का फैसला देते हुए सेवायतन अस्पताल को आदेश दिया कि वह सत्यनारायण शर्मा को उक्त राशि अदा करें। *(रा.प., 23.04.16)*

उपभोक्ता संरक्षण कानून में होगा संशोधनः बन्द होंगे भ्रामक विज्ञापन

यह तेल लगाने से गंजे सिर पर बाल उग जाएंगे, इस कैप्सूल को खाने से मोटापा कम हो जाएगा। लोगों को बरगलाने वाले ऐसे विज्ञापन अब बन्द होंगे। सरकार इन पर रोक लगाने के लिए इसी मानसून सत्र के दौरान उपभोक्ता संरक्षण कानून में संशोधन का प्रस्ताव लाएगी।

खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सरकार केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण भी बनाने जा रही है। ताकि सही तरीके से निगरानी की जा सके। सरकार ने मैगी मामला भी भ्रामक विज्ञापन के चलते कार्रवाई के लिए केन्द्रीय उपभोक्ता आयोग को सौंपा है।

उन्होंने कहा कि अभी तक फूड सेफ्टी एजेंसी तभी कार्रवाई करती थी जब कोई शिकायत करे। अब इसे पॉवरफुल बनाया जा रहा है, वह अब कभी भी बिना शिकायत के खाद्य सामग्री के किसी भी मामले में जांच कर कार्रवाई कर सकेगी।

कानून में यह होंगे बदलाव

- *जुर्माना बढ़ेगा। जिला स्तर पर एक करोड़, राज्य स्तर पर 10 करोड़ व राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग 100 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकेगा।*
- *ई-कॉमर्स मामले देखने के लिए नए कानून में व्यवस्था होगी।*
- *उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण मौजूदा फोरम से अलग होगा। वह किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान ले सकेगा तथा कार्रवाई कर सकेगा।*

ग्राहक सुविधा केन्द्र

भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सौजन्य से 'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है। आप उपभोक्ता सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी अथवा शिकायत के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

ग्राहक सुविधा केन्द्र
कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स), डी-218 ए, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
ई-मेल: gsk@cuts.org फोन +091.141.4015395

स्त्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, डे.न्यू.: डेलीन्यूज

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.513 3259 फैक्सः 228 2485, टेलीफैक्सः 401 5395, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।